



2026:AHC:68343-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 12145 वर्ष 2026

कुसुम कुमारी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दुर्गा कुमारी, प्रवीण कुमार सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 40

माननीय न्यायमूर्ति श्री सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति श्री गरिमा प्रसाद

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता श्री आरके पाल को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है: -

"1. जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज (अनुलग्नक संख्या-1) द्वारा रिट याचिका पर पारित दिनांक 22.4.2022 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

2. रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-4 के अपने आवेदन 15.12.2021 पर मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के तहत मुआवजा प्रदान करने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें..."

3. दिनांक 22.5.2022 के आक्षेपित आदेश द्वारा, अपने पति शेर की मृत्यु के कारण मुख्यमंत्री दुर्गा कल्याण योजना (इसके बाद "योजना" के रूप में



संदर्भित) के तहत मुआवजा देने के याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि मृतक कृषक नहीं थी।

4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश विकृत है और पूरी तरह से दिमाग के अनुप्रयोग की कमी से ग्रस्त है। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता ने पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत की थी जिसमें यह प्रदर्शित किया गया था कि मृतक बटाईदार के रूप में कृषि गतिविधियों में लगा हुआ था।

5. 28.02.2020 के सरकारी परिपत्र पर भरोसा किया गया है, जो बटाई-फसल सहित कृषि गतिविधियों में लगे भूमिहीन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए "किसान" को परिभाषित करता है। परिपत्र में आगे प्रावधान है कि ऐसे बटाईदारों की पहचान भूमि मालिक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के माध्यम से या उपयुक्त मामलों में, ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा स्थापित की जा सकती है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने नेबू लाल की पत्नी गुलाब देवी का हलफनामा प्रस्तुत किया था, जिसने दुर्घटना के फसल वर्ष में मृतक को गाटा संख्या-00326 में अपनी जमीन बटाईदार (बटाईदार) के रूप में दी थी। इसके अलावा, ग्राम प्रधान ने यह भी प्रमाणित किया है कि मृतक बटाईदार के रूप में कृषि कार्य कर रहा था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिपक्षियों ने राज्य सरकार द्वारा जारी 28.02.2020 के परिपत्र पर विचार किए बिना मुआवजे के दावे को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है।

7. तत्सम्य विपरीत, स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार, मृतक कृषि गतिविधियों में संलग्न नहीं था। यह तर्क दिया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने रिपोर्ट पर विचार किया और दावे को खारिज करते हुए एक तर्कसंगत आदेश पारित किया।

8. हमने पक्षगण के अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

9. दिनांक 28.02.2020 का परिपत्र, जो योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, पात्रता मानदंड निर्धारित करता है, और खंड 2 में "किसान" शब्द को



परिभाषित करता है, जिसमें खंड 2(3) के तहत बटाईदार के रूप में लगे भूमिहीन व्यक्ति शामिल हैं, जो निम्नानुसार हैं: -

"2. पात्रता (किसान की परिभाषा)-

यह योजना ऐसे किसानों के लिए है जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और जो आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता का शिकार हैं। "किसान" शब्द निम्नलिखित को संदर्भित करता है:

... (3) भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे के माध्यम से या बटाई-फसल के आधार पर प्राप्त भूमि पर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं, और जिनकी आजीविका के प्राथमिक साधनों में इस तरह पट्टे पर दी गई भूमि पर किए गए ऐसे कृषि कार्य शामिल हैं या बटाईदार-फसल के आधार पर ली गई हैं। 'पट्टेदार' शब्द में असामी पट्टेदार, सरकारी पट्टेदार, और निजी पट्टेदार शामिल होंगे।

10. पट्टेदार या बटाईदार की स्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 28.02.2020 के परिपत्र के प्रस्तर-3(बी) में निर्दिष्ट हैं, जो निम्नानुसार है: -

"3. पट्टेदारों/बटाईदारों की पहचान:

(b) बटाईदार (बटाईदार) की पहचान

बटाईदार (बटाईदार) की पहचान करने के लिए, निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित में से कोई भी प्रमाण पत्र केवल किसान की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में "मुख्यमंत्री कृषक विकास कल्याण योजना" के तहत सहायता देने के उद्देश्य से मान्य होगा। हालांकि, ये प्रमाण पत्र किसी अन्य उद्देश्य के लिए, या भूमि स्वामित्व का दावा करने आदि के लिए मान्य नहीं होंगे:

(1) भूस्वामी या उसके उत्तराधिकारी/कानूनी उत्तराधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि दुर्घटना में मृत्यु हो गई या विकलांग हो गए व्यक्ति ने दुर्घटना के फसल वर्ष में अपनी भूमि पर बटाईदार के आधार पर खेती की थी। या



(2) यदि भूस्वामी उपलब्ध नहीं है, तो क्षेत्र के ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर के तहत दिया गया एक प्रमाण पत्र कि उक्त प्रभावित व्यक्ति दुर्घटना के फसल वर्ष में भूमिधारक की भूमि पर बटाईदार (बटाईदार) था।

इसके अलावा, बटाईदारों (बटाईदार) की पहचान के संबंध में, राजस्व विभाग के स्थानीय अधिकारी, निरीक्षण के बाद, खुद को संतुष्ट करेंगे कि केवल पात्र व्यक्तियों को ही योजना का लाभ उठाने की अनुमति है।

11. अभिलेखों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने नेबू लाल की पत्नी गुलाब देवी का प्रमाण पत्र दाखिल किया था, साथ ही योजना के तहत अपने दावे के समर्थन में ग्राम प्रधान द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र भी दाखिल किया था। हालाँकि, दिनांक 22.04.2022 का आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से दिमाग न लगाने को दर्शाता है, क्योंकि यह अभिलेखों पर रखे गए दस्तावेजों पर विचार किए बिना पूरी तरह से लेखपाल की रिपोर्ट पर आगे बढ़ता है, जिसमें यह स्थापित करने वाले प्रमाण पत्र भी शामिल हैं कि मृतक बटाईदार के रूप में काम कर रहा था।

12. इस प्रकार आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से दिमाग के अनुप्रयोग को दर्शाता है। प्राधिकरण प्रासंगिक साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहा है और योजना के स्पष्ट प्रावधानों और शासी परिपत्र की अनदेखी की है। योजना के उद्देश्य को प्रभावी बनाने में सहायता करने के बजाय, दावे को एक संकीर्ण और यांत्रिक विचार पर खारिज कर दिया गया है, जिससे उस उद्देश्य को विफल कर दिया गया है जिसके लिए योजना तैयार की गई है। ऐसा दृष्टिकोण कल्याणकारी कानून की भावना के विपरीत है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है।

13. प्रस्तुत मामले में, याचिकाकर्ता ने संतोषजनक रूप से स्थापित किया है कि मृतक एक बटाईदार (बटाईदार) के रूप में कृषि गतिविधियों में लगा हुआ था, और इस प्रकार योजना के तहत "किसान" की परिभाषा के अंतर्गत आता है।



14. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज द्वारा पारित दिनांक 22.04.2022 के आक्षेपित आदेश को एतद्वारा रद्द/अपास्त किया जाता है।

15. कानून के अनुसार और यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ता के दावे पर नए सिरे से पुनर्विचार करने के लिए मामले को जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को भेजा जाता है। उक्त कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर।

मार्च 31, 2026

राकेश

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)